

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सकल्प

पटना-15 दिनांक 16-11-2009

बिहार पदों एवं वेतनों की रिक्तियों में आयोग (आ.वि.सं. 1) के अधीन (अनुसूची-2) के क्रमांक-18 पर बढई जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उक्त स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-113 पर शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध को दाय्य करेगा और ऐसी सूचियों किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9(1) के तहत राज्य सरकार को सलाह दी है कि "राज्य के पिछड़े की सूची (पिछड़े वर्गों की अनुसूची-2) के क्रमांक-18 पर दर्ज बढई जाति को विलोपित किया जाय और बढई जाति को अति पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में स्वतंत्र रूप से समावेशित/शामिल किया जाय।"

3. अतः राज्य सरकार ने मती-भौति विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं वेतनों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-18 पर बढई जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उक्त स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-113 पर शामिल किया जाय।

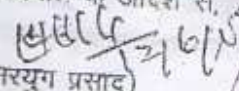
उक्त विलोपन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्वद, नगर पालिका अर्थात् सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों की (अनुसूची-1) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को दाय्य अन्य सुविधाएं अनुमान्य होगी।

7/11/09
कर्मचारियों की सूची
06/11/09
3945

जा.
49350
16-11-09

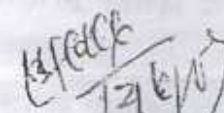
R.No
169
28-10-09

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए इसकी प्रति गहालेखाकार बिहार पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधानसभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 (सरयुग प्रसाद)
 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक- 11/वि.10-अ.पि.व.आ.-04/08का 2844 / पटना-15, दिनांक 12-6-2009

प्रतिलिपि- अर्थात्कः राजकीय मुद्रणालय, गुलजायान, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक- 11/वि.10-अ.पि.व.आ.-04/08का 2844 / पटना-15 दिनांक 12-6-2009

FRK NO. :


Nov. 05 2009 12:50PM P2

बिहार राज्यपाल के आदेश से, बिहार राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधानसभा, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पंचदों को अविलम्ब सूचित कर दें।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक 1485, दिनांक - 18-11-09
 प्रतिलिपि- बिहार कल्याण पदाधिकारी-सारा-644/अनुमण्डल पदाधिकारी-सारा-644/महोपा/मोनपुर/सभी-प्रमण्डल-विभागाध्यक्ष/सभी-विभागाध्यक्ष का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव।

M
 R.MC
 469
 28-10